उत्तराखण्ड शासन

गृह अनुभाग–5

अधिसूचना

18 सितम्बर, 2025 ई0

संख्या–1398/XX-5-2025-05(09)2023–राज्यपाल साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या–10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या–46, सन् 2023) की धारा 396 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013 में संशोधन करने के दृष्टिगत निम्नलिखित योजना बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

उत्तराखण्ड अपराध से पीडित सहायता (संशोधन) योजना, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस योजना का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता (संशोधन) योजना, 2025 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
योजना में संशोधन	2.	उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013 (जिसे आगे उक्त योजना कहा गया है) में "सहायता" शब्द के स्थान पर जहां–जहां वह आते हैं "सहायता/क्षतिपूर्ति" शब्द और चिन्ह् रख दिये जायेंगे।
प्रस्तर 3 में संशोधन	3.	उक्त योजना के प्रस्तर 3(1) में शब्द "अनुसूची–1" के पश्चात् शब्द "एवं अनुसूची–2" को अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे।
अनुसूची–2 अतःस्थापन	4.	उक्त योजना की अनुसूची–1 के पश्चात् नयी अनुसूची–2 निम्नवत् अन्त :स्थापित कर दी जाएगी, अर्थात् :–

अनुसूची–2

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन पीड़ित।

क्र0सं0	हानि या क्षति का विवरण।	सहायता/क्षतिपूर्ति की धनराशि की न्यूनतम सीमा।	सहायता/क्षतिपूर्ति की धनराशि की अधिकतम सीमा।
1.	प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा–4)	रू0 1,00,000/–	रू0 7,00,000/–
2.	गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा–6)	रू0 1,00,000/–	रू0 7,00,000/–
3.	लैंगिक हमला (धारा–7)	रू0 50,000/–	रू0 1,00,000/–
4.	गुरूत्तर लैंगिक हमला (धारा–9)	रू0 50,000/–	रू0 2,00,000/–
5.	लैंगिक उत्पीड़न (धारा–11)	रू0 20,000/–	रू0 1,00,000/–
6.	अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग (धारा–14)।	रू0 50,000/–	रू0 1,00,000/–

आज्ञा से,

शैलेश बगौली,

सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1398/XX-5-2025-05(09)2023 Dated- September 18, 2025 for general information.

NOTIFICATION

September 18, 2025

No. 1398/XX-5-2025-05(09)2023--In exercise of powers conferred section 396 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897) with a view to amend the Uttarakhand Victim From Crime Assistance Scheme, 2013, the Governor is pleased to allow to make the following Scheme:-

Uttarakhand Victim From Crime Assistance (Amendment) Scheme, 2025

Short title and commencement

1. (1) This scheme may be called the Uttarakhand Victim From Crime Assistance (Amendment) Scheme, 2025.

(2) It shall come into force at once.

Amendment in the Scheme

2. In the Uttarakhand Victim From Crime Assistance Scheme, 2013 (hereinafter referred to as the said Scheme), for the word "assistance" wherever they occur, the words and symbol "assistance/ compensation" shall be substituted.

Amendment in Para 3

3. In para 3(1) of the said Scheme, after the word "Schedule-1", the Word " and Schedule-2 shall be inserted.

Schedule-2 insertion

4. A new Schedule-2 shall be inserted after Schedule-1 of the said Scheme as follows, namely:-

Schedule-2

Victims under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

Ser No.	Description of loss or damage.	Minimum limit of amount of assistance/ compensation.	Maximum limit of amount of assistance/compensation.
1.	Penetrative sexual assault (Section-4)	Rs 1,00,000/-	Rs 7,00,000/-
2.	Aggravated penetrative sexual	Rs 1,00,000/-	Rs 7,00,000/-

	assault (Section-6)		
3.	Sexual assault (Section-7)	Rs 50,000/-	Rs 1,00,000/-
4.	Aggravated sexual assault (Section-9)	Rs 50,000/-	Rs 2,00,000/-
5.	Sexual harassment (Section-11)	Rs 20,000/-	Rs 1,00,000/-
6.	Use of child for pornographic purposes (Section-14)	Rs 50,000/-	Rs 1,00,000/-

By Order,

SHAILESH BAGAULI,

Secretary.

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 20–09–2025, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित––]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 34 गृह/452–15–10–2025–50 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)